साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 24-30 जुलाई 2023 वर्ष-9, अंक-15

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

बैंकों को कहा- ज्यादा ब्याज पर ली गई राशि का उच्च ब्याज दरों में निवेश करें

ब्याज चुकाने के बाद भी डिफॉल्टर 11.19 लाख किसानों पर 3356 करोड़ का कर्ज

- ब्याज के पैसा से मार्कफेड और अपेक्स बैंक ने कर ली अपने कर्ज की भरपाई
- 5 ज्यादा कर्जदार जिलों में सीहोर-विदिशा के साथ छिंदवाड़ा शामिल
- सरकार ने डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का 2122.71 करोड़ ब्याज भरा

भोपाल। जागत गांव हमार

बीस साल तक के पुराने कर्ज का ब्याज चुकने के बाद भी 11 लाख 18 हजार 916 डिफॉल्टर किसानों पर 3356 करोड़ रुपए मूल ऋण के बकाया है। पांच सबसे ज्यादा कर्जदार जिलों में सीहोर, विदिशा के साथ छिंदवाड़ा भी शामिल हैं। सबसे कम कर्ज 6.80 करोड़ रुपए अनूपपुर जिले के किसानों पर है। ब्याज चुकने के बाद अब जिन किसानों की केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) की जितनी लिमिट बढ़ेगी, उन्हें उतना नया कर्ज मिल मिलेगा।

जिनकी नहीं बढ़ेगी, वे नया कर्ज नहीं ले पाएंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने इन डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का 2122.71 करोड़ रुपए ब्याज भरा है। यह पैसा पैक्स सोसायटी के पास राज्य सरकार की अंशपूंजी के तौर पर गया, जो फिलहाल 1419.04 करोड़ रुपए है। सहकारिता विभाग के अफसरों का कहना है कि ब्याज भरने की स्कीम आने के बाद सात लाख 90 हजार डिफॉल्टर किसानों ने फॉर्म भरा था, जिनका ब्याज माफ हो गया। चूंकि यह स्कीम नवंबर 2023 तक है, इसलिए अभी भी आवेदन पैक्स सोसायटी को मिल रहे हैं।

100 करोड़ से ज्यादा कर्ज वाले जिले

जिला	डिफॉल्टर	कर्ज
मंदसौर	46,763	196.02
छिंदवाड़ा	37,120	160.69
सीहोर	36,648	152.54
छतरपुर	44,302	141.34
विदिशा	31,863	141.15
खरगोन	25,147	129.21
बैतूल	35,935	113.31
उज्जैन	27,367	112.90
सागर	52,817	105.64
सिवनी	43,321	104.84
खंडवा	25,109	103.91
बालाघाट	42,928	102.97

(कर्ज की राशि करोड़ में)

दोनों बैंक गबन-जांच से जूझ रहे

बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, खरगोन, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, भोपाल, बैतूल, विदिशा, सीहोर, शहडोल, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर और शाजापुर जिला बैंक को कहा गया कि मार्कफेड का 282.67 करोड़, ज्यादा ब्याज पर ली गई राशि का 610.64 करोड़ और 161.44 करोड़ उच्च ब्याज दरों में निवेश किया जाए, जिसका बाद में फसल ऋण वितरण में उपयोग हो। गुना और शिवपुरी जिला बैंक को कहा गया है कि वह ब्याज माफी में मिले पैसे का उपयोग उच्च स्तर से निर्णय के बाद करेगा। ये दोनों बैंक गबन और जांच से जूझ रहे हैं।

न पैक्स में गया और न बैंकों को मिला

राज्य सरकार से अंशपूंजी के रूप में जो ब्याज के करीब 1500 करोड़ रुपए पैक्स (प्राथमिक साख सहकारी समितियां) को मिले, उससे मार्कफेड और अपेक्स बैंक ने कर्ज की भरपाई कर ली। पैसा पैक्स से जिला सहकारी बैंकों में बुलवा लिया। उसके बाद कर्ज की भरपाई करवा ली गई। साफ है कि ब्याज का पैसा न पैक्स के पास गया और न ही बैंकों को मिला। डिफॉल्टर किसान का ब्याज जरूर पैक्स में शून्य हो गया।

मार्कफेड ने ले लिए 400 करोड़ रुपए

पैसा जारी होने के तुरंत बाद ही सहकारिता विभाग की ओर से निर्देश जारी हो गए। इसमें जिला बैंकों जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, सागर, दमोह, रायसेन, होशंगाबाद, राजगढ़, दतिया, ग्वालियर, मुरैना और भिंड को कहा गया कि मार्कफेड का 111.75 करोड़, अपेक्स बैंक का 147.42 करोड़ और ज्यादा ब्याज पर बाजार से जो पैसा लिया गया है, उसका 105.12 करोड़ रुपए चुकाया जाए।

-जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई

पांच सरपंच और दो सचिवों के खिलाफ जेल वारंट जारी

शिवपुरी। लोकेराम मौर्य

पंचायत के जिन प्रतिनिधियों पर पंचायत के विकास का जिम्मा था। उन्होंने ही पंचायत की संपत्ति और विकास के लिए आई राशि हड़प ली। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों के खिलाफ सीईओ जिला पंचायत उमराव सिंह मरावी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पोहरी और खनियाधाना क्षेत्र के पांच तत्कालीन सरपंच और दो तत्कालीन सचिवों के खिलाफ जेल वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा पंचायत की एलईडी, इनवर्टर व फर्नीचर हड़पने के साथ-साथ लाखों रुपए का गबन किया गया है। नोटिस के बावजूद जब सरपंच और सचिवों ने गबन की गई सामग्री और राशि जमा नहीं की तो इनके खिलाफ पंचायत अधिनियम की धारा-92(2) के तहत 30 दिन की सिविल जेल के लिए संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से जेल वारंट जारी किए गए हैं। सीईओ की इस कार्रवाई से गबन करने वाले सरपंच और सचिवों में हड़कंप मच गया। जिन पांच सरपंच व सचिवों के खिलाफ जेल वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई है, उनमें खनियाधाना की ग्राम पंचायत मसूरी के तत्कालीन सचिव गजेंद्र लोधी पर 10 लाख 99 हजार 358 रुपए की वसूली है, जबकि रही पंचायत के तत्कालीन सचिव मुकेश पारासर पर 29,282 रुपए की। इसी तरह तत्कालीन सरपंचों की बात करें तो खनियाधाना की मानपुर पंचायत के तत्कालीन सरपंच अशोक खंगार पर 85 हजार 278, पोहरी की भरसूला पंचायत की तत्कालीन सरपंच सुमित्रा शर्मा पर 12,500, खड़ीचरा पंचायत के तत्कालीन सरपंच कैलाश सिंह यादव पर 40 हजार और हिंडोरखेड़ी के तत्कालीन सरपंच नरेंद्र वंशकार पर 61 हजार रुपए की वसूली शेष है। खनियाधाना हर्षरा पंचायत की तत्कालीन सरपंच सावित्री बाई से शासकीय समाग्री सहित एलईडी, इनवर्टर व फर्नीचर की वसूली किया जाना है।

आलीराजपुर जिले के किसान ने अपनाई आधुनिक खेती

- आम महोत्सव में जीते चार राष्ट्रीय पुरस्कार
- 25 एकड़ में 26 प्रकार के आम के पौधे लगाए

भोपाल। मप्र में उद्यानिकी और आधुनिक खेती के क्षेत्र में कई नवाचार हो रहे हैं। सरकार से मिले प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के चलते लोग परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। खेती उनके लिए अच्छे लाभ का व्यवसाय बन रही है। एक समय किसान ने खेती में होने वाले नुकसान से हताश होकर इसे प्राथमिकता देना कम कर दिया था। इसके बाद मप्र उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों को उन्नत फसलों के लिए प्रशिक्षण दिया, जिससे किसानों ने आधुनिक खेती को अपनाया और अब अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। ऐसे ही एक किसान हैं आलीराजपुर के छोटा उंडवा गांव निवासी युवराज सिंह। उन्होंने अपने बगीचे में 26 प्रकार के आम के पेड़ लगाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए आम महोत्सव में युवराज सिंह को चार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

आईटी प्रोफेशनल ने लिखी गुड़ की मीठी कहानी

गन्ने के बचे भूसे से बना रहे क्रॉकरी, पेपर प्लेट्स

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर शुरू से ही अपने देसी गुड़ के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध रहा है। यह उसकी अब पहचान तक बन चुकी है। नरसिंहपुर की पहचान चीनी उत्पादन के लिए है। यहां के किसान गुड़ बनाते तो थे, लेकिन पुरानी पद्धतियों से बने गुड़ की डिमांड कम थी। इसी कमी को आईटी प्रोफेशनल अंकित शर्मा ने पहचाना और एक सक्सेस स्टोरी लिख दी। अंकित को नरसिंहपुर में अहसास हुआ कि गुड़ के क्षेत्र में एक अच्छे स्टार्टअप की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर रिसर्च उनके काम आया। उन्होंने साफ-सफाई से गुड़ बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया। उसके बाद यह सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया में गुड़ का पोषण बरकरार रहे। साथ ही इससे बने उत्पाद नए जमाने के ग्राहकों को पसंद आए। जब उन्होंने अपने कृषि स्टार्टअप फ्यूचर फार्मर्स एलएलपी की शुरुआत की तो उनके मन में बस एक ही बात थी कि गुड़ उत्पादन के अस्वच्छ तरीके को बदलना है। इस पूरी प्रक्रिया में उनके गुड़ के उत्पादों को इंसानों का हाथ तक नहीं लगता। यह पूरा मशीन से हो जाता है।

ब्रांड का नाम 'ग्लैडेन' | अंकित ने अपने ब्रांड का नाम 'ग्लैडेन' रखा है। अंकित कहते हैं कि पहले वह एक किसान है, दूसरा निर्माता और तीसरा एक ब्रांड के मालिक हैं। अंकित अब सिर्फ गुड़ और गुड़ से बने उत्पाद नहीं बेच रहे हैं। वह गन्ने के अवशेष से बनी क्रॉकरी, पेपर प्लेट आदि भी बेच रहे हैं। कंपनी साथ ही नए जमाने के ग्राहकों के लिए कैंडी और गुड़ पाउडर भी बना रही है। कंपनी ने हाल ही में सर्विस सेक्टर में भी प्रवेश किया है। हालांकि अंकित यहीं नहीं रुकने वाले हैं।

किसान बने मददगार

अंकित को गुड़ और इससे बने उत्पादों के उत्पादन के लिए गन्ने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वह किसानों से मदद लेते हैं। वह छोटे और बड़े किसानों के साथ काम करते हैं। अंकित के लिए भी यह सफर आसान नहीं था। वह गन्ने की खेती की बारीकियों को तो सीख गए लेकिन उन्हें रिटेल, मार्केटिंग इत्यादि चीजों में महारत हासिल करनी थी। इसके लिए उन्हें एक कंपनी के कार्यक्रम ने काफी मदद की।

कलेक्टर, सीईओ, विधायक, जिपं उपाध्यक्ष सहित 3 गांवों के 600 लोग हुए शामिल

तीन गांव के 600 लोगों ने लगाए 3333 अमरूद के पौधे जलस्तर में सुधार के साथ ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

खरगोन। जागत गांव हमार

कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशन में पौधारोपण के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार देने की शुरुआत हुई है। बुधवार को भगवानपुरा जनपद के वसाली गांव में अमरूद की विदेशी प्रजाति थाईवान पिंक के 3333 पौधे लगाएं गए। 3 हेक्टेयर में लगाएं गए पौधों की खासियत यह है कि ये मात्र 8 माह में फल देने प्रारम्भ कर देंगे।

इसी उद्देश्य के साथ इस प्रजाति के पौधें लगाएं ताकि जब फल आने लगे तो एफपीओ के माध्यम से इसे एक बड़े व्यापार के रूप में किसानों को जोड़ा जा सकें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बनाएं गए बाग की निगरानी उद्यानिकी विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। पौधरोपण में तीन गांवों के करीब 600 लोगों ने सहभागिता की। इस दौरान जनपद सीईओ पवन शाह, डॉ. चेतन कलमे, उद्यानिकी उपसंचालक केके गिरवाल, मनरेगा पीओ श्याम रघुवंशी, शर्मिला बड़ोले, सुचिता खोड़े, महिला बाल विकास के अधिकारी और मनरेगा का अमला उपस्थित रहा।

जल ही जीवन है, तो पौधें रोजगार हैं| कलेक्टर ने पौधरोपण के बाद कहा कि जिस तरह जल ही जीवन है, उसी तरह पौधे रोजगार है। कई तरह के पौधों से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है तो अमरूद से भी यहां के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रजाति के पौधों से 500 ग्राम से 600 ग्राम के अमरूद पकते हैं। यही अमरूद रोजगार देगा। यह जिले का एक आदर्श और अनोखा बागीचा होगा। बच्चों के प्रति गांव की जिम्मेदारी कलेक्टर ने भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों से कहां कि स्कूल, आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केन्द्र समय पर नहीं खुलते हैं तो हमें फोटो भेंजे। स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। यह सब भी देखना गांव की जिम्मेदारी है। सामूहिक सहभागिता से कई अच्छे कार्य होते मैंने भी देखा हे। आप लोग भी ऐसे कार्यों की शुरुआत करें। गांव की मौलिक व्यवस्था में अपना योगदान दें।

वृक्ष और पानी आत्मा और शरीर के समान

जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा ने ग्रामीणों ने कहा कि वृक्ष और पानी, आत्मा और शरीर के समान है। दोनों का अपना-अपना अस्तित्व है। वृक्ष नहीं होंगे तो पानी संभव नहीं शरीर नहीं होगा तो आत्मा भी सम्भव नहीं। इसलिए पौधें लगाकर पानी बचाना होगा। आप लोगों ने गर्मी में पानी की कमी देखी है। तो कम से कम पेड़ पौधें लगाकर हम जमीन में पानी देंगे तो ही गर्मी में पानी मिल पायेगा। हमको पौधें लगाने का कार्य जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी किसान या व्यक्ति 200 पौधें शासकीय सहयोग से सकता है। कार्यक्रम के दौरान भगवानपुरा विधायक केदार डावर ने भी सम्बोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों की मांग रखी। साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापूसिंह परिहार ने भी संबोधित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में खरपतवार नियत्रंण का भी पढ़ाया पाठ

वैज्ञानिकों ने दी फसल उत्पादन की जानकारी

सागर। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर में एक दिवसीय अंत: सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (फसल उत्पादन एव पौध संरक्षण) का आयोजन डॉ. केएस यादव, प्रधान वैज्ञानिक एव प्रमुख के मार्गदर्शन मे किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एमपी दुबे के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप संचालक कृषि बीएल मालवीय जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉ. ममता सिंह के द्वारा बदलते जलवायु में सोयाबीन एव खरीफ में लगाए जाने वाले फसलों के उत्पादन के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

डॉ. एमपी दुबे के द्वारा खरीफ मौसम में उगाये जाने वाले फसलों में खरपतवार नियत्रंण किस प्रकार करें। इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विशिष्ट अतिथि के द्वारा पर्यावरण का जीवन के लिए महत्व तथा बदलते जलवायु परिवर्तन के विविधीकरण खेती तथा मानव के ऊपर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के ऊपर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए किया जागरुक

डॉ. केएस यादव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के द्वारा इस अवसर पर बदलते जलवायु परिवेश में जल, सुरक्षित मृदा प्रबंधन, मोटे अनाज की उन्नत खेती एवं उसका महत्व, प्राकृतिक खेती तथा खरीफ में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों जैसे सोयाबीन, उड़द, अरहर आदि की उन्नत कृषि उत्पादन तकनीकों तथा कम एवं अधिक वर्षा होने की परिस्थितियों में आकस्मिक प्लान पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में परियोजना संचालक आत्मा जितेन्द्र सिंह राजपूत के द्वारा जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. वैशाली शर्मा, वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान) ने जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान की। डीपी सिंह, तकनीकी अधिकारी के द्वारा प्राकृतिक खेती पर जानकारी प्रदान दी गई एवं आभार प्रदर्शन किया गया।

स्थापना दिवसः जैविक खेती और मृदा परीक्षण पर किया मंथन

रीवा। भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 95वें स्थापना दिवस के अवसर कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा द्वारा तक कृषकों के लिए विभिन्न विस्तार गतिविधियों एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संचालक विस्तार सेवाये ज. नेकृविवि, जबलपुर डॉ. डीपी शर्मा एवं अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, रीवा डॉ. एसके पयासी के मार्गदर्शन में एवं डॉ. एके पांडेय प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृ. वि. के. रीवा के निर्देशन में उक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तकनीकी दिवस एवं प्रदर्शनी व परिचर्चा में कृषकों को विभिन्न तकनीकों की जानकारी विषय पर केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा ग्राम कंजी, देवरा एवं खोखंम में दी गई। एके पटेल, अखिलेश कुमार, डॉ. स्मिता सिंह, संदीप कुमार शर्मा डॉ. संजय सिंह, के. एस. बघेल द्वारा उक्त तीन दिवसीय कार्यक्रमों में क्रमशः पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, मृदा प्रबंधन एवं मौसम विज्ञान से संबंधित उन्नत तकनीकी पर विस्तृत चर्चा की गयी। उक्त तीन दिवसीय कार्यक्रम में एफपीओ स्वयं सहायता समूह एवं कृषक व महिलाओं में सक्रियता पूर्वक भाग लिया।

चयनित किसानों की एक अगस्त को निकाली जाएगी लॉटरी

सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि में जोखिम कम करने, वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने एवं भरपूर पैदावार के लिए किसानों के पास सिंचाई के उपयुक्त साधन होना जरूरी है। ऐसे में सभी किसानों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र भारी सब्सिडी पर दिए जाते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों के किसान विभिन्न योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान सिंचाई उपकरणों के लिए 31 जुलाई 2023 के दौरान पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध ऑनलाइन लॉटरी एक अगस्त 2023 को निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान सिंचाई यंत्र खरीद कर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पास बुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
- बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल

इन योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

- देश में किसानों को उनके क्षेत्र कि आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाएँ चलाई जा रही है। जिनके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र दिये जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने निम्न योजनाओं के तहत राज्य के किसानों से आवेदन मांगे हैं-
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन - स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन) - स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं- स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम (जिले कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, निवाड़ी के लिए।)
- राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन - स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा - स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट (जिले जबलपुर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, नरसिंगपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरोली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल के लिए।)
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान- पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) (जिले कटनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी,अनूपपुर के लिए।)
- बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन- स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़,छतरपुर, दतिया, निवाड़ी शामिल हैं।

सिंचाई यंत्रों पर कितना अनुदान दिया जाएगा

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 55 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

अनुदान पर सिंचाई यंत्र लेने के लिये आवेदन यहां करें

मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है । अत: जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या सीएससी सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी चैनित और प्रतीक्षित किसानों की सूची

10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही सरकार आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र सरकार द्वारा किसानों को सस्ते में कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेती में काम आने वाले टॉप 10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। किसान लक्ष्य के अनुसार इस योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदन कर सकेंगे। संचालनालय , कृषि अभियांत्रिकी , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 17 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे से 27 जुलाई तक कृषि यंत्र पावर टिलर -8 बीएचपी से अधिक, पावर वीडर , पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित), क्लीनर-कम-ग्रेडर, सीड ड्रिल एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ग्राउंडनट प्लांटर/ रेन्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/मल्टीक्रॉप प्लान्टर के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं । प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 28 जुलाई 2023 को सम्पादित की जाएगी। लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 03 बजे प्रदर्शित की जाएगी।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इन्हें कृषि यंत्र की लागत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। आप ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर की सहायता से कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी ले सकते हैं। इस सब्सिडी कैलकुलेटर से आप यह जान पाएंगे कि किस यंत्र पर आपको लागत मूल्य के अनुसार कितनी सब्सिडी विभाग से मिल सकती है। कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नानुसार धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

धरोहर राशि इस प्रकार

- पावर टिलर -8 बी.एच.पी से अधिक - रू. 5000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- क्लीनर-कम-ग्रेडर - रू. 5000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- पावर वीडर - रू. 2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित)- रू.2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- सीड ड्रिल - रू. 2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल/जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइज़र ड्रिल/ग्राउंडनट प्लांटर/ रेन्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/मल्टीक्रॉप प्लान्टर - रू. 2000 /- धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

नोट:- 1. पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

2. बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन आवेदन निरस्त हो जाएगा।

मंडी बोर्ड सभागार में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

49 मंडियों के कर्मचारियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण

एगमार्कनेट पोर्टल पर अच्छा काम करने वाले दो सहायक उपनिरीक्षक सम्मानित

भोपाल। एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा एंट्री के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डीएमआई भोपाल तथा आंचलिक कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में मंडी बोर्ड सभागार में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भोपाल संभाग की 49 मंडियों के डाटा रिपोर्टिंग करने वाले कर्मचारियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण पोर्टल से संबंधित समस्त जानकारी आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रबंध संचालक गौतम सिंह व द्वारा एगमार्कनेट पोर्टल पर अच्छा काम करने वाले दो सहायक उपनिरीक्षकों का सम्मान भी किया गया।

क्या है एगमार्कनेट

एगमार्कनेट पोर्टल मंडी समितियों में दैनिक कृषि उपजों की आवक एवं भाव को दर्ज करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया पोर्टल है, जिसमे सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अपने क्षेत्रान्तर्गत मंडी समितियों में होने वाली दैनिक कृषि उपजों की आवक एवं भाव को दर्ज करते है। उक्त महत्वपूर्ण कार्य को सम्पादित करने में मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भारत में द्वितीय स्थान पर है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीएमआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रसाद चक्रवर्ती, मंडी बोर्ड के अपर संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठ, आंचलिक कार्यालय भोपाल की संयुक्त संचालक रितु चौहान, एन.आई.सी. भोपाल के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक मुशर्रफ सुल्तान, चीफ प्रोग्रामर संदीप चौबे, सहायक संचालक लक्ष्मण वास्केल के साथ-साथ डीएमआई के अधिकारीगण, मंडी समितियों से आए हुए प्रतिभागी उपस्थित रहे।

लघुधान्य फसलों में अर्न्तवर्तीय फसलों का महत्व

» डॉ. मनीषा श्याम
» डॉ. डीएन श्रीवास
» डॉ. अंकुर खरे
» डॉ. राहुल शर्मा
» डॉ. अंचल केशरी
» डॉ. रूपेश वर्मा
» डॉ. पंकज चौबे

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान लघु धान्य परियोजना क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिण्डौरी (म.प्र.)

ज्वार तथा बाजरा जैसे मोटे अनाजों के अतिरिक्त अन्य लघुधान्य फसलें जैसे-कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, चीना, कंगनी एवं बासारा फसलें हैं, जो भारत के अनेकों भागों में उगायी जाती है। ये फसलें जहां भूमि दूसरे उत्तम धान्य उगाने योग्य नहीं रहती हैं। ये शीघ्र तैयार होने वाली फसलें हैं।

लघु धान्य फसलें गरीब आदिवासी कृषकों के वैकल्पिक खाद्यान्न की श्रेणी में आती है, क्योंकि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितम्बर में जब कोई खाद्य फसल तैयार नहीं होती और इन दिनों अन्य खाद्यान्न फसल की बोनी मंहगी हो जाती है, जिसे गरीब किसान नहीं खरीद सकते, उस समय 60 से 70 दिनों में पकने वाली कुटकी एवं चीना, कंगनी इसके बाद सांवा, कोदो व रागी पककर तैयार हो जाती है, फिर अन्य खाद्यान्न फसल जैसे- मक्का, धान आदि तो मिलता ही है। जिन कृषकों के पास मात्र हल्की जमीन ही हो, जिसमें अन्य किसी प्रकार की फसलें नहीं ली जा सकती हो उसमें वैकल्पिक रूप से लघुधान्य फसलों को लगाया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि लघुधान्य फसलों में पाये जाने वाले पोषक तत्वों एवं रोगों को मिटाने की असाधारण क्षमता के कारण इनका व्यापरिक स्तर पर विपरण शुरू हो गया है। व्यापरिक स्तर पर यह बहुत ही कम मूल्य की मानी जाने वाली फसलें है, परंतु फिर भी ऐक्षिक या वैकल्पिक खाद्यान्न है, इन फसलों में गेहूं एवं चावल जैसे अनाज वाली फसलों की तुलना में सूखा सहने की विलक्षण क्षमता है।

चूंकि ये मुख्य खाद्यान्न फसलों में न आने के कारण अन्य फसलों की तुलना में क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी उपेक्षित रही है। ये केवल जगलों में या भर्रा क्षेत्रों रहने वाले आदिवासी कृषकों का एक मुख्य आहार के रूप में ही रहा है, परंतु दिनोदिन क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास एवं परिश्राम से कुछ नई उन्नत जातियां क्षेत्रीय एवं मध्यप्रदेश में लघुधान्य फसलों को उगाने वाले क्षेत्र हेतु विमोचित की गई है एवं आदिवासी कृषकों के बीच में व्यापक रूप से इसका प्रचार-प्रसार किया गया है एवं अधिक उपज होने कारण इन किस्मों को अपनाया जा रहा है।

कोदो के साथ में अरहर अंर्तवर्तीय फसल पद्धतिः मध्यप्रदेश में अधिकांशतः लघुधान्य फसल उगाने वाले जिले जैसे कि डिण्डौरी, मण्डला, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, छिदवाड़ा, बैतूल, झाबुआ एवं खण्डवा आते है। मप्र के इन जिलों में लघुधान्य फसलें मुख्यतः कंकरीली - पत्थरीली पहाडियों ढालानों एवं कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में की जाती है इनको उगाने वाले सभी क्षेत्रों के आदिवासी कृषकों की वर्तमान आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। साथ ही उनके पास जोत का रकवा भी सीमित है, किंतु अपने स्वास्थ्य जीवनयापन करने के लिये दलहन, तिलहन व अन्य फसलों से होने वाले अनाजों की आवष्यकता पड़ती है। इसी को देखते हुए परम्परागत तरीके से कृषकों द्वारा मिश्रित खेती की जाती रही है, किंतु इन क्षेत्रों अन्य जिलों की तुलना में खासकर डिण्डौरी, उमरिया, अनूपपुर एवं मण्डला जिले में ठंड के दिनो में तापक्रम अत्यधिक कम हो जाने के कारण मुख्य दलहन फसलों में पाला लगने की संभावना बनी रहती है, इन क्षेत्रों रबी में बोवाई क्षेत्र काफी कम होता है, अतः रबी में लगने वाली दलहन फसलों की खेती बहुत कम रकवें में हो पाती है।

एकल एवं मिश्रित खेतीः मुख्य फसल के साथ ही साथ जो अन्य उसी समय की फसल लगाई जाती है, उससे कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, साथ ही जब मुख्य फसल खराब हो जाती है, तब साथ में लगी मिश्रित फसल या अतिरिक्त फसल बचाकर लाभ लिया जा सकता है। बहुधा यह देखा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के कृषक कोदो एवं कुटकी के बीज के साथ ज्वार, अरहर, तिल, पटषन, उडद, लोबिया, ग्वार एवं रागी के बीज मिलाकर छिटकवा विधि द्वारा बोनी करते हैं। अरहर व कोदो मिश्रित खेती करने से अरहर में लगे कीटों की रोगथाम के लिए पूरे क्षेत्र में दवा का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अरहर के पौधे एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से तो नहीं रहते हैं। अतः अनुसंधान प्रयोगों एवं शोध कार्यों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि कोदो एवं कुटकी के साथ अर्न्तवर्तीय फसल के रूप में यदि तिल, लोबिया, उडद/मूगं, ग्वार एवं अरहर तथा रागी के साथ रामतिल, तिल, सोयाबीन व अरहर की खेती की जाये तो अधिक लाभ प्राप्त होता है।

रागी एवं लोबिया अन्तवर्तीय फसल पद्धतिः कृषि शोध कार्यो एवं अनुसंधान परिणामों से यह प्रदर्षित हुआ है कि मिश्रित खेती एवं एकल फसल की तुलना में अर्न्तवर्तीय फसलों द्वारा अधिक लाभ प्राप्त होता है। अर्न्तवर्तीय फसलों के चयन व अनुपात ज्ञात करने हेतु अनुसंधान शोध कार्य, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिण्डौरी में विगत कई वर्षों से किये जा रहे हैं, जिनके परिणामों से ज्ञात हुआ है कि यदि कोदो व कुटकी के साथ 4:2 में अरहर की फसल लगाई जाए तो उपज में सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है।

अतः आदिवासी अंचलों के कृषकों को सलाह दी जाती है कि कोदो , कुटकी एवं अन्य लघुधान्य फसलों को शुद्ध फसल के रूप में न लेकर इनकी स्थान पर उपरोक्त अनुपात (4:2) में अरहर की फसल अर्न्तवर्तीय खेती के रूप में की जानी चाहिए। कृषकों के खेतों में प्रदर्शन के माध्यम से इस अनुसंधान तकनीकी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और कृषकों द्वारा इस पद्धिति को रूचिपूर्वक अपना जा रहा है। इस प्रकार कोदो कुटकी एवं रागी के साथ अन्य अर्न्तवर्तीय फसलें बोकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।

जमीन के अंदर पानी को जहरीला बना रहा है कीटनाशक

दुनिया भर में हर साल खेतों में करीब 30 लाख टन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें से करीब 70,000 टन कीटनाशक जमीन के अंदर रिसकर भूजल में मिल रहा है। जो जमीन के अंदर मौजूद पानी को भी जहरीला बना रहा है। शोध में सामने आया है कि खेतों से यह कीटनाशक लम्बी दूरी तय करके समुद्रों तक पहुंच सकते हैं। वहीं उपयोग होने वाले 80 फीसदी कीटनाशक अणुओं में विभाजित होकर या उपोउत्पाद के रुप में फसलों के आसपास ही मिट्टी में विघटित हो जाते हैं।

देखा जाए तो कभी फसलों के लिए वरदान समझे जाने वाले कीटनाशक आज अभिशाप बन गए हैं। जो पर्यावरण के साथ-साथ, पानी, मिट्टी, हवा और खाद्य पदार्थों को भी जहरीला बना रहे हैं। आज यह न केवल जैवविविधता बल्कि इंसानो के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गए हैं। इनका अंधाधुंध तरीके से खेतों में होता उपयोग, किसानों के लिए भी खतरा हैं क्योंकि यह मिट्टी की गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि खेतों से निकलने वाला यह कीटनाशक 730 टन प्रतिवर्ष की दर से नदियों में घुल रहा है। इसी का नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर नदियों के करीब 13,000 किलोमीटर हिस्से में इन कीटनाशकों की मात्रा सुरक्षित सीमा को पार कर गई है। जो उसमें रहने वाले समुद्री जीवों और वनस्पति के लिए खतरा बन चुकी है। साथ ही यह नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं।

मैगी के मुताबिक भले ही इसमें से नदियों में पहुंचने वाले कीटनाशकों की 0.1 फीसदी मात्रा ज्यादा न लगती हो लेकिन पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए इन कीटनाशकों की यह थोड़ी मात्रा ही बहुत है।

यह जानकारी सिडनी विश्वविद्यालय और खाद्य और कृषि संगठन से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर में 12 जुलाई 2023 को प्रकाशित हुए हैं। गौरतलब है कि अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले 92 कीटनाशकों और उनके भौगोलिक वितरण का विश्लेषण किया है।

हर साल समुद्रों तक भी पहुंच रहा 710 टन कीटनाशकः रिसर्च के अनुसार हालांकि मिट्टी में रिस रहे कीटनाशकों की तुलना में केवल 1.1 फीसदी कीटनाशक ही नदियों में मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े पैमाने पर नदियों और उसकी जैवविविधता को प्रभावित कर रहा है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि इन कीटनाशकों में से करीब 710 टन हर साल समुद्रों तक पहुंच रहा है जो वहां भी समुद्री जीवन और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन रहा है।

इस बारे में सिडनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता फेडेरिको मैगी का कहना है कि, हमारे अध्ययन से पता चला है कि कीटनाशक अपने मूल स्रोत से बहुत दूर तक भटकते हैं। कई मामलों में ये केमिकल नीचे की ओर लंबा रास्ता तय करते हैं और बहुत कम मात्रा में, समुद्र तक पहुंच जाते हैं।

शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने अध्ययन में केवल खेतों में उपयोग होने वाले कीटनाशकों को शामिल किया है। इसमें उन्होंने लोगों द्वारा अपने बगीचों, घरों, सार्वजनिक स्थानों, और जलीय कृषि में उपयोग के साथ पहले उपयोग किए गए कीटनाशकों की गणना नहीं की है। इसका मतलब है कि लोगों और पारिस्थितिक तंत्र का इन कीटनाशकों के संपर्क में आने का जोखिम उनके अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकता है।

जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक अन्य शोध से पता चला है कि कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग की वजह से दुनिया में खेतीयोग्य जमीन का करीब 64 फीसदी हिस्सा यानी 2.45 करोड़ किलोमीटर हिस्सा खतरे में है। वहीं करीब एक तिहाई जमीन (31 फीसदी) पर इसका गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अध्ययन के अनुसार इसकी वजह से भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में वाटरशेड्स पर कीटनाशकों के कारण होते प्रदूषण का खतरा कहीं ज्यादा है।

ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि कीटनाशकों के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उसकी मात्रा के साथ-साथ विषाक्तता और जोखिम को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जीवों के लिए बहुत ज्यादा जहरीले कीटनाशकों की बहुत कम मात्रा भी उनके लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर इनके प्रभावों को देखते हुए सरकारों को कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरकों और कीटनाशक से जुड़े आंकड़ों का खुलासा करना चाहिए। शोधकर्ता मैगी का भी कहना है कि कीटनाशकों के उपयोग में वैश्विक कमी तभी संभव है, जब इस तरह की पहला को किसानों के परामर्श से बनाया और कार्यान्वित किया जाता है।

अमृत सरोवर' से बनेगा पूसा जल संरक्षण का केंद्र

दल्ली में मौजूद पूसा संस्थान के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। पूसा के अन्दर ही एक बड़े अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर यह महत्वपूर्ण जानकारी पूसा के निदेशक डॉ एके सिंह द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि जल है तो कल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश भर में अमृत सरोवर योजना चलाई जा रही है। हमारी आगे की पीढ़ी के लिए जल संरक्षण बहुत जरुरी है। इसलिए 'अमृत सरोवर' एक प्रमुख जल संरक्षण के लिए बड़ी योजना है। इसी योजना से प्रेरित होकर पूसा संस्थान के भीतर एक बड़े अमृत सरोवर का निर्माण करवाया गया है। आपको बता दें कि अमृत सरोवर योजना जल संचय, जल संग्रहण, और जल संरक्षण के लिए अद्वितीय एवं उदाहरणीय विकल्प है। इसी को अपनाते हुए एक अमृत सरोवर का निर्माण पूसा संस्थान द्वारा भी किया गया है ताकि कृषि अनुसंधान में जल की महत्वपूर्णता को प्रदर्शित किया जा सके।

आपको बता दें पूसा अमृत सरोवर का विस्तार 2.5 एकड़ में किया गया है और यह संस्थान के अनुसंधान फार्म के 60 प्रतिशत जल आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखता है। इस सरोवर का प्राथमिक उद्देश्य वर्षा के पानी को संग्रहित करना है और इसे कृषि क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराना है। यह संरक्षित जल स्रोतों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय है जो समुद्र तल से पानी की खपत को कम करने और प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। इस सरोवर से अब तक 4 करोड़ लीटर पानी की बचत की जा चुकी है। पूसा संस्थान के निदेशक डॉ. अशोक कुमार सिंह ने पूसा अमृत सरोवर के महत्व को बताया है और इसका उपयोग कृषि और जल संरक्षण में कैसे किया जा सकता है। इस पहल के माध्यम से, जल संरक्षण के महत्व को जागृत करने और सामरिक जल संग्रहण के लिए प्रेरित किया जाता है। यह संसाधन कृषि में जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रमुख कदम है और कृषि क्षेत्र में समृद्धि को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

पूसा में इस अमृत सरोवर के निर्माण से कई लाभ मिल सकेंगे, जिसमे पानी की किल्लत से निजत मिलेगी साथ ही खेती करने में पानी की उपलब्धता बनी रहेंगी।

कीटों से बचाव के लिए हर सप्ताह नीम के तेल का छिड़काव कर करना चाहिए

किसान कम से कम लागत में कमा सकते हैं अधिक मुनाफा

तेज पत्ता की बढ़ती बाजार मांग: किसानों के लिए मुनाफे का सौदा हो रही खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

तेज पत्ता की बढ़ती बाजार मांग के कारण तेज पत्ता की खेती मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। तेज पत्ता की खेती करना बेहद ही सरल होने के साथ ही काफी सस्ता भी है। इसकी खेती से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तेज पत्ता कई काम आता है। इसका हमारी खाने में उपयोग होने के साथ ही हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके अलावा तेज पत्ता का इस्तेमाल कई आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। बहरहाल अभी बात हम इसकी खेती की करेंगे कि किस प्रकार इसकी खेती करके हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कम लागत में तेज पत्ता की खेती कैसे की जाएं।

तेज पत्ता की खेती पर सब्सिडी और लाभ- इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अब बात करें इससे होने वाली आमदनी की तो तेजपत्ते के एक पौधे से करीब 3000 से 5000 रुपए तक प्रति वर्ष तथा इसी तरह के 25 पौधों से 75,000 से 1,25,000 रुपए प्रति वर्ष कमाई की जा सकती है।

तेज पत्ता में पाएं जाने वाले पोषक तत्व- तेज पत्ता में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो प्रति 100 ग्राम तेज पत्ता में पानी-5.44 ग्राम, ऊर्जा-313 कैलोरी, प्रोटीन-7.61 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट-74.97 ग्राम, फैट-8.36 ग्राम, फाइबर-26.3 ग्राम, कैल्शियम-834 मिलीग्राम, आयरन-43.00 मिलीग्राम, विटामिन-सी 46.5 मिलीग्राम मात्रा पाई जाती है।

तेज पत्ता के पौधों की रोपाई का तरीका

नए पौधों को लेयरिंग, या कलम के द्वारा उगाया जाता है, क्योंकि बीज से उगाना मुश्किल हो सकता है। बे पेड़ को बीज से उगाना मुश्किल होता है, जिसका आंशिक कारण है बीज का कम अंकुरण दर और लम्बी अंकुरण अवधि. फली हटाए हुए ताजे बीज का अंकुरण दर आमतौर पर 40 प्रतिशत होता है, जबकि सूखे बीज और/या फली सहित बीज का अंकुरण दर और भी कम होता है। इसके अलावा, बे लॉरेल के बीज की अंकुरण अवधि 50 दिन या उससे अधिक होती है, जो अंकुरित होने से पहले बीज के सड़ जाने के खतरे को बढ़ा देता है। इसे देखते हुए खेत में इसके पौधे का रोपण किया जाना ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके पौधों का रोपण करते पौधे से पौधे की दूरी 4 से 6 मीटर रखनी चाहिए। ध्यान रहे कि खेत में पानी की समुचित व्यवस्था हो। इन्हें पाले से भी बचाने की जरूरत होती है। कीटों से बचाव के लिए हर सप्ताह नीम के तेल का छिड़काव कर करना चाहिए।

तेज पत्ता के खाने में उपयोग| तेज पत्ता का इस्तेमाल विशेषकर अमेरिका व यूरोप, भारत सहित कई देशों में खाने में किया जाता है। उनका इस्तेमाल सूप, दमपुख्त, मांस, समुद्री भोजन और सब्जियों के व्यंजन में किया जाता है। इन पत्तियों को अक्सर इनके पूरे आकार में इस्तेमाल किया जाता है और परोसने से पहले हटा दिया जाता है। भारतीय और पाकिस्तान में इसका उपयोग अक्सर बिरयानी और अन्य मसालेदार व्यंजनों में तथा गरम मसाले के रूप में रसोई में रोज इस्तेमाल किया जाता है।

कहां-कहां होती है इसकी खेती| इसका ज्यादातर उत्पादन करने वाले देशों में भारत, रूस, मध्य अमेरिका, इटली, फ्रांस और उत्तर अमेरिका और बेल्जियम आदि हैं। वहीं भारत में इसका ज्यादातर उत्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक के अलावा उतरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है।

तेज पत्ता की खेती कैसे करें| वैसे तो तेज पत्ता की खेती सभी प्रकार की भूमि या मिट्टी में की जा सकती है। लेकिन इसके लिए 6 से 8 पीएच मान वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। इसकी खेती से पहले भूमि को तैयार करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी की दो से तीन बार अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए। वहीं खेत से खरपतवारों को साफ कर देना चाहिए। इसके बाद जैविक खाद का उपयोग करें।

तेज पत्ता में कब-कब करें सिंचाई

तेज पत्ता में विशेष सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों के मौसम में सप्ताह में एक बार सिंचाई की जानी चाहिए। वहीं बरसात के मौसम में मानसून देरी से आए तो सिंचाई कर सकते हैं वर्ना तो बारिश का पानी ही इसके लिए पर्याप्त है। सर्दियों में इसे पाले से बचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं।

तेज पत्ता की कटाई

करीब 6 वर्ष में इसका पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसकी पत्तियों को काटकर छाया में सुखाना चाहिए। अगर तेल निकालने के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो आसवन यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।

सरकार देती है अनुदान

अगर आप तेजपत्ता की खेती करते हो तो आपको सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी. इसकी खेती करने वाले किसानों को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की ओर से 30 फीसदी अनुदान दिया जाता है। सब्सिडी पाने के लिए आपको बोर्ड के पास आवेदन करना होगा। इसके लिए बोर्ड समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करता रहता है।

कितनी होगी कमाई

अब अगर हम मुनाफे की बात करें तो तेजपत्ता के एक पौधे से आप सालाना 5 हजार रुपये तक कमा सकते हैं। वहीं अगर आप तेजपत्ता के 25 पौधे लगाते हैं तो आपको सालाना 75 हजार से 1 लाख 25 हजार तक कमाई हो सकती है। अगर आप ज्यादा पौधे लगाएंगे तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी।

लौकी की खेती: देश के लगभग हर इलाके में लौकी की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही

उन्नत किस्मों से किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी

भोपाल। जागत गांव हमार

लौकी एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। भारत में लौकी को बहुत से नामों से जाना जाता है जैसे घिया, दूधी और कलाबश। लौकी की सिर्फ सब्जी ही नहीं बनती, बल्कि रायते, हलवे से लेकर स्वादिष्ट मिठाई तक बनती है। हरी सब्जियों में लौकी बहुत लोकप्रिय है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर व कई विटामिन्स होते हैं। लौकी की खेती भी बहुत मुश्किल नहीं है। सही जलवायु और उचित मिट्टी मिलने पर यह आसानी से उग जाती है। अन्य फसलों की तरह ही लौकी की भी कई किस्में हैं जो बाकियों के मुकाबले उन्नत मानी जाती हैं, क्योंकि यह अच्छी पैदावार देती है। देश के लगभग हर इलाके में लौकी की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। यदि आप भी लौकी की खेती करते हैं, तो आपको इन किस्मों की जानकारी होनी चाहिए।

लौकी की उन्नत किस्म

अर्का नूतन| लौकी की इस किस्म की पैदावार भी अच्छी होती है। ये हल्के हरे रंग की और लंबी होती है। इस किस्म की प्रति हेक्टेयर 46 टन तक की पैदावार होती है और 56 दिनों में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है।

अर्का श्रेयस| प्रति हेक्टेयर 48 टन तक की पैदावार देने वाली लौकी की यह किस्म लंबी नहीं, बल्कि थोड़ी गोलाई में और मोटी होती है। यह खुले परागण वाली किस्म है जो 60 दिनों में तैयार हो जाती है।

अर्का बहार| यह किस्म बरसात और गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और 50 से 60 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। जहां तक पैदावार की बात है, तो प्रति हेक्टेयर 450 से 500 क्विंटल होती है।

अर्का गंगा| प्रति हेक्टेयर 58 टन तक की पैदावार देने वाली लौकी की यह किस्म अंडाकार आकार की होती है और रंग हरा होता है। यह 56 दिनों में तैयार हो जाती है।

काशी गंगा| यह किस्म अधिक पैदावार देती है। यानी इसकी खेती करके किसान आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। इस किस्म की लौकी मीडियम साइज की होती है, रंग हरा होता है और लंबाई एक से डेढ़ फीट होती है। बीज लगाने के 50 से 55 दिन बाद फल लगते हैं। इनके अलावा काशी बहार, पूसा नवीन, नरेंद्र रश्मि, पूसा संदेश आदि लौकी की उन्नत किस्में हैं, जो अच्छी पैदावार देती हैं।

जलवायु और मिट्टी लौकी की खेती के लिए गर्म व आद्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी बोवनी गर्मी और बरसात के मौसम में की जाती है। दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। यदि आप भी लौकी की खेती से मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इन किस्मों की बोवनी करके आमदनी बढ़ा सकते हैं। लौकी एक आसानी से लगने वाली सब्जी है। इसे लगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और एक बार पौधा यदि अच्छी तरह लग जाता है, तो खूब पैदावार होती है।

अधिक पैदावार के लिए इस तरह करें कपास की बोवनी

भोपाल। देश में कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। व्यावसायिक जगत में यह श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कपास की मानसून के आने पर ही बुआई की जाती है। यदि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, तो मई महीने में भी इसकी बोवनी की जा सकती है। किसान इसकी बोवनी के लिए सीड-कम-फर्टीड्रिल अथवा प्लांटर का प्रयोग कर सकते हैं। कपास की खेती रेतीली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है। बोवनी के लिए अमेरिका, संकर और देसी कपास का क्रमशः प्रति हेक्टेयर 15-20, 4-5 और 10-12 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। देसी कपास अथवा अमेरिकन कपास के लिए 60 × 30 सेमी तथा संकर किस्मों के लिए 90 × 40 सेमी पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए।

उपयुक्त किस्में

किसानों को बोवनी के लिए उनके क्षेत्र के अनुसार ही अनुशंसित किस्मों का उपयोग करना चाहिए। कपास की कुछ संकर प्रजातियां जैसे - लक्ष्मी, एचएस 45, एच.एस. 6, एलएच 144, एचएल 1556, एफ. 1861, एफ 1378, एफ 1378, एफ. 846 एवं देसी प्रजातियां जैसे - एच. 777, एचडी 1, एच. 974, एचडी 107, डीएस 5, एलडी 327 उगाई जा सकती है।

बोवनी से पहले करें बीजोपचार

किसानों को बोवनी से पहले बीज को प्रति किग्रा 2.5 ग्राम कार्बेन्डाजिम या कैप्टान दवा से उपचारित करना चाहिए। बीजोपचार से फसल को राइजोक्टोनिया जड़ गलन, फ्यूजेरियम उकठा और अन्य मृदाजनित फफूंद से होने वाली व्याधियों से बचाया जा सकता है। कार्बेन्डाजिम अन्तप्रवाही (सिस्टमिक) रसायन है, जिससे फसल को प्राथमिक अवस्था में रोगों के आक्रमण से बचाया जा सकता है। इमिडाक्लोरोप्रिड 7.0 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 20 ग्राम/ किग्रा. बीज उपचारित करने से 40-60 दिनों तक रस चूसक कीटों से सुरक्षा मिलती है। दीमक से बचाव के लिए 10 मिली क्लोरोपाइरीफास मिलाकर बीज पर छिडक दें तथा 30-40 मिनट छाया में सुखाकर बुआई कर दें। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परिक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए।

कृषि संगोष्टी में वैज्ञानिकों ने कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न प्रदर्शन इकाईयों को दिखाया

प्राकृतिक खेती कर किसान बचाएं पर्यावरण

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा 95वां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम गांवों एवं कार्यालय में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार के मार्गदर्शन में किया गया। साथ ही केंद्र के वैज्ञानिक डा् एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह एवं जयपाल छिगारहा उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम ग्राम गरौली विकासखण्ड बल्देवगढ़ में किया गया। इस स्थापना दिवस पर प्रभारी अधिष्ठाता, डॉ. डीएस तोमर, केंद्र प्रमुख डॉ. बीएस किरार एवं कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. एके श्रीवास्तव, डॉ. एमके नायक एवं डॉ. राघवेन्द्र सिसोदिया द्वारा गांव में कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्र के प्रमुख डॉ. बीएस किरार ने व्याख्यान देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महत्व को बताया। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. डीएस तोमर ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र कृषकों की बीच जागरूकता एवं नई तकनीकों का प्रचार-प्रसार करता है, जिससे कृषकों में जागरूकता आती है।

यह कार्यक्रम द्वितीय दिवस कृषि विज्ञान केंद्र में संपन्न हुआ, जिसमें कृषकों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया। वर्तमान में हो रहे रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से मृदा का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण खराब हो रहा है। जिससे मानव स्वास्थ्य पर कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसलिए कृषक भाइयों द्वारा प्राकृतिक खेती कर पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न प्रदर्शन इकाईयों को दिखाया गया।

तृतीय दिवस में इस कार्यक्रम में श्री अन्न की खेती पर कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें श्री अन्न वाली लघु धान्य फसलें जैसे दृ ज्वारए बाजराए रागीए सांवाए कोदो-कंगनी-कुटकी-चीना-एमरेंथस आदि है। इन फसलों को उगाकर तथा मानव उपयोग में लाकर कई बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन फसलों पर रोग एवं कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम होता है तथा इन फसलों में पोषक तत्वों की भी भरपूर मात्रा पायी जाती है। संस्था द्वारा तीन दिवसीय तकनीकी दिवस श्री अन्न एवं प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण देकर संपन्न हुआ।

केवीके द्वारा गरौली गांव में श्रीअन्न फसलों पर प्रशिक्षण

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा 16 जुलाई 2023 को गांव गरौली विकासखंड बल्देवगढ़ में 95वां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर श्री अन्न फसलों की उत्पादन तकनीक और भोजन में उनके महत्व पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में डॉ. बी.एस. किरार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. डीएस तोमर, प्रभारी अधिष्ठाता, डॉ. एके श्रीवास्तव, डॉ. एमके नायक एवं डॉ. राघवेन्द्र सिसोदिया वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़ द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में डॉ. बीएस किरार ने लघु धान्य बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कोदो, कंगनी, कुटकी, चीना आदि की वैज्ञानिक खेती के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला साथ ही इनकी जैविक या प्राकृतिक खेती अर्थात् बिना रासायनिक उर्वरक और दवायों की खेती करने की सलाह दी गयी। डॉ. डीएस तोमर ने लघु धान्य फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके नियंत्रण के बारे में बताया साथ ही लघु धान्य फसलों को फिर से अपने भोजन में शामिल करने की सलाह डी गयी। इनमें रेशा, कैल्शियम, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है। डॉ. एमके नायक द्वारा लघु धान्य फसलों के प्रमुख कीट एवं उनके नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉ. एके श्रीवास्तव एवं डॉ. राघवेन्द्र सिसोदिया द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के बारे में विस्तार से बताया। मौसम विज्ञान के कई ऐपों के द्वारा किसानों को मौसम के बारे में पहले ही जानकारी दी जाती है कि जिले एवं विकास खंड में किस दिन कितनी वर्षात होने वाली है या तेज हवायें, लू या पाला पड़ने की संभावना के बारे में मौसम वैज्ञानिक किसानों को नियमित समसामायिकी सलाह देते रहते हैं। इस कार्यक्रम में गांव के प्रधान अध्यापक राजपूत एवं युवा कृषक मिथलेश राजपूत का विशेष सहयोग रहा।

कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में मनाया स्थापना दिवस

बालाघाट। जिले के किरनापुर में स्थित राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में 17 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95 वा स्थापना दिवस समारोह और मैनेज द्वारा आदान विक्रेताओं का कृषि प्रसार सेवाओं में डिप्लोमा एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स सत्र 2022-23 के अंतर्गत नोडल प्रशिक्षण सस्थान कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के सभागार में 14 अप्रैल 2022 से प्रारंभ प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डा.आर.एल राउत, धुवारे उपस्थित रहे। इस संबध में राउत ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95 वा स्थापना दिवस समारोह और मैनेज द्वारा आदान विक्रेताओं का कृषि प्रसार सेवाओं में डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट सीईओ आरसी पटले उपस्थित रहे। पटले ने बालाघाट, किरनापुर, लांजी, वारासिवनी, खेरलाजी, कटंगी, लालबर्रा से प्रशिक्षणकर्ता को संबोधित करते हुए कहा किकृषि का आधारभूत ज्ञान जरूरी है। व्यवसाय के साथ किसानों की सेवा करना कृषि आदान का लक्ष्य रखें। पटले ने कहा कि समय के साथ अपडेट रहना आवश्यक है ताकि हम अपने उद्देश्य को हासिल कर सके। इसके अलावा पटले ने किसानों को दी जाने वाली शून्य प्रतिशत ब्याज दर, केसीसी, बीमा, खाद, बीज के अलावा कॉपरेटिव बैंक बालाघाट के माध्यम से किसानों को दी जानी वाली सुविधाओं की जानकारी से अवगत कराया गया।

80 हजार पशुओं को लगा लम्पी स्कीन रोग प्रतिबंधात्मक टीका

देवास। जिले में पशुपालन विभाग द्वारा जिले में पशुओं का लम्पी स्कीन रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में रोग संभावित क्षेत्रों का चयन कर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि जिले के अब तक लगभग 80 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में पशुओं को अन्य रोगों से बचाव के लिए भी टीके लगाये जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष लम्पी स्कीन संक्रामक रोग से पशु रोगग्रस्त हो गए थे और कई पशुओं की मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए इस वर्ष पशुपालन विभाग द्वारा एहतियात के तौर पर रोग संभावित क्षेत्रों का चयन कर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि अन्य पशुओं में इसका संक्रमण न फैले।

लाईव वेबकॉस्ट प्रोग्राम में किसानों को मुर्गीपालन के महत्व को बताया

मंदसौर। 95वें आईसीएआर स्थापना दिवस एवं प्रौद्योगिकी दिवस को कृषि विज्ञान केन्द्र, मन्दसौर पर लाईव वेबकॉस्ट प्रोग्राम दिखाया एवं साथ ही केन्द्र पर दिवस को मनाया गया। आईसीएआर हर साल 16 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस वर्ष से इसे स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में दिनांक 16 से 18 जुलाई 2023 तक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषक एवं कृषक महिलाओं ने आईसीएआर स्थापना दिवस एवं तकनीकी दिवस के उपलक्ष्य में तकनीकी सेंशन लाईव

सुना। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. जीएस चुंडावत द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना के बारे में जानकारी दी और कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन में उक्त संस्थान का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पहेड़ा, मैनपुरिया, लुनेहड़ा, कामलिया गांवों के 52 कृषक एवं कृषक महिलाओं ने भाग लिया। डॉ. एसपी त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक (गृह विज्ञान) ने मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दी और बाजरा के उत्पाद बनाकर प्रदर्शित किया गया।

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा-सरकार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही

कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ के बजट प्रावधान किया गया

देश में कृषि और बागवानी उत्पाद से होने वाली निर्यात आय 50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) ने कल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं आईसीएआर सोसायटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने पिछले 94 वर्षों की आईसीएआर की ऐतिहासिक यात्रा और इसकी समग्र उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने आह्वान किया कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र है और देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से किसानों के लाभ के लिए विभिन्न नए मिशन कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि में नई तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत के कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर पसंद किया जा रहा है और मोटे अनाज को महत्व मिल रहा है। यह किसानों और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के कारण हो रहा है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि और बागवानी उत्पाद से होने वाली निर्यात आय 50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है। उन्होंने बताया कि सरकार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है और पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ एक अलग मिशन शुरू किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों और किसानों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप देश न केवल कई वस्तुओं में आत्मनिर्भर बन गया बल्कि खाद्य वस्तुओं का निर्यातक भी बन गया।

कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने पर फोकस

डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (आईसीएआर) ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि बड़ी मात्रा में कृषि और कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने आईसीएआर द्वारा प्राप्त उपलब्धियों जैसे कि खाद्यान्न की 346 किस्मों का विकास, बागवानी फसलों की 99 किस्में, कुशल फसल प्रणाली क्षेत्रों की मैपिंग, 24 फसलों के लिए प्रजनन कार्यक्रम, 28 नए उपकरण और मशीनरी, कोरोना वायरस और लम्पी रोग के टीके, नए निदान, नई मछली नस्लों का प्रजनन प्रोटोकॉल, फार्म परीक्षणों पर 47088 का संचालन और नई प्रौद्योगिकियों पर 2।99 लाख फ्रंट लाइन प्रदर्शन आदि के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विभिन्न उद्योगों के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 58 पेटेंट और 711 प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। व्यावसायीकरण के लिए कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक-उद्योग इंटरफ़ेस बैठकें भी साइड इवेंट के रूप में आयोजित की जाती हैं। इससे पहले संजय गर्ग, अतिरिक्त सचिव (डेयर) और सचिव आईसीएआर ने स्वागत भाषण दिया। इस कार्यक्रम में आईसीएआर शासकीय निकाय के सदस्यों, आईसीएआर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों, वैज्ञानिकों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, किसानों, कृषि उद्यमियों ने भी भाग लिया।

किसानों को विशेषताओं और गुणों से अवगत कराया गया

मूंगफली फसल की उत्पादन तकनीक पर किसानों को किया गया प्रशिक्षित

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव एवं कृषि महाविद्यालय से वैज्ञानिक डॉ. एमके नायक, डॉ. एके श्रीवास्तव, डॉ. राघवेंद्र सिसोदिया एवं दीपक कुडो द्वारा गांव गुना, विकासखंड बल्देवगढ़ में मूंगफली की उत्पादन तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों द्वारा मूंगफली फसल की उन्नत किस्मों जीजेजी 32, टीजी 37 ए, आईसीजीवी 350 आदि की विशेषताओं एवं गुणों से अवगत कराया गया। टीकमगढ़ जिले में विगत 3-4 वर्षों से मूंगफली का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। मूंगफली फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए कम से कम एक निंदाई-गुड़ाई का कार्य बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर अवश्य करना चाहिए। जिससे जड़ों का फैलाव अच्छा होता है साथ ही भूमि में वायु संचार भी बढ़ जाता है और गुड़ाई का कार्य करने से फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य स्वतः ही हो जाता है। जिससे मूंगफली के तांतू (पेंगिग) आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। निंदाई-गुड़ाई में श्रमिक की समस्या होने पर शाकनाशी दवा खड़ी फसल में बुवाई के 20 से 25 दिन में इमेजेथापायर 40 मिली सक्रिय तत्व प्रति एकड़ 150-200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में प्रमुख कीट सफेद लट (व्हाइट ग्रब), बिहार रोमिल इल्ली, माहू एवं दीमक आदि हैं। इनके हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति और इनके प्रबंधन के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा विस्तार से बताया गया।

प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें

रस चूसक कीटों जैसे माहू, थ्रिप्स, सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट 30 ई.सी. दवा 2 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पत्ती खाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए क्विनालफॉस 25 ईसी. दवा 400 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली के प्रमुख रोगों में टिक्का, कॉलर और तना गलन एवं रोजेट रोग का प्रकोप देखा जाता है। वायरस जनित रोगों को फैलाने वाली सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें और टिक्का रोग से बचाव के लिए डाइथेन एम-45 दवा 2 ग्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

बढ़ी चिंता: किसानों के लिए महंगी साबित हो रही खेतों में धान की रोपाई

मजदूरी 3 हजार बीघा, ट्रैक्टर का किराया 2 हजार प्रति घंटा

श्योपुर। जागत गांव हमार

जिले में इन दिनों धान की रोपाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। हर गांव में किसान अपने खेतों में धान की रोपाई में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बीच खेतों की मिट्टी को मचाने के लिए चलने वाले ट्रैक्टर का किराया सहित मजदूरी में हुई बढ़ोत्तरी किसानों के गले की फांस बनी हुई है। धान की रोपाई कर रहे किसानों को अनाप-शनाप मजदूरी और किराया चुकाना पड़ रहा है। जिसके कारण उनके छोटे-छोटे रकबों में धान की रोपाई की लागत बढ़ रही है।

उल्लेखनीय है कि, पिछले कुछ वर्षों में जिले में बारिश के सीजन में धान की रोपाई की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। जिसके कारण जिले में धान का रकबा भी बढ़ा है। हालांकि अभी बारिश न होने के कारण खेतों में बोर से पानी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को बिजली भी महंगी मिल रही है। जिले भर में एक साथ चल रहे धान की रोपाई के चलते अचानक से ट्रैक्टर के किराए और धान की रोपाई की मजदूरी बढ़ गई है। इस फसल को छोटे-बड़े किसान अपने खेतों में लगाते हैं। जिनमें से लघु और सीमांत किसान इसकी एक से दो एकड़ या कई जगहों पर आधा एकड़ जगह में भी बोवनी करते हैं। लेकिन इस साल मजदूरी और किराए की दरों में काफी बढ़ोत्तरी हो गई है। जिसके कारण छोटे किसानों की लागत भी बढ़ रही है।

बीते सालों में धान की फसल की रोपाई दर लगभग दो से ढाई हजार रुपए प्रति बीघा थी जो कि इस वर्ष में बढ़कर 3 हजार के लगभग हो गई है। इसी प्रकार ट्रैक्टर का किराया जो कि पिछले साल 1800 रुपए था वह भी बढ़कर 2 हजार रुपए के आसपास पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि जिस धान की फसल में पिछले वर्ष प्रति बीघा 8 हजार रुपए का खर्च आता था, वहीं इस वर्ष खर्चा बढ़कर 12 हजार के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में किसानों को धान की रोपाई में खर्चा बढ़ने से काफी परेशानी आ रही है।

कृषि उद्यानिकी तकनीक की कॉन्फेंस में बोले मंत्री कमल पटेल

खेती आज भी गांव में रोजगार का सबसे सशक्त साधन

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किसान समर्पण भाव से परिश्रम कर रहा है। आज भी गांव में कृषि ही रोजगार का सबसे सशक्त और प्रभावी साधन है। मंत्री कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आईएफसी की कृषि उद्यानिकी तकनीक की प्रथम राउंडटेबल कॉन्फेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आशा जताई कि आज की कॉन्फ्रेंस में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर होने वाली चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कॉन्फ्रेंस में फूड प्रोसेसिंग एण्ड मशीनरी, मार्केटिंग लिंकेज, नर्सरी डेवलपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी (इक्विपमेंट एवं टूलस एण्ड इनोवेशन्स) चर्चा के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। कॉन्फेंस में एसीएस उद्यानिकी जेएन कंसोटिया, एसीएस कृषि अशोक वर्णवाल, सचिव एमएसएमई पी. नरहरि, सीईओ एसआरएलएम एलएम बेलवाल, संचालक उद्यानिकी निधि निवेदिता, ऐग-टेक सोल्यूशन कंपनीज, कृषि वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी, प्रगतिशील कृषक, विषय-विशेषज्ञ सहित उद्यान अधिकारी एवं तकनीकी स्टाफ मौजूद रहा।

साहूकारों के कर्ज से मुक्ति मिली

मंत्री ने कहा कि मप्र में किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। जिससे किसानों को साहूकारों के कर्ज से मुक्ति मिली है। प्रदेश देश में कृषि अधोसंरचना मद में 4 हजार करोड़ की राशि किसान हित में व्यय कर प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में चना, मसूर, सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ कर किसानों को हजारों करोड़ रूपये से लाभांवित किया है। प्रदेश की मंडियों में प्रतिदिन उपार्जन की क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों के मंडी में बार-बार आने से धन एवं समय के अपव्यय को रोकने में मदद मिली है। इसका सीधा लाभ किसानों की आमदनी पर हुआ है।

यह देश किसानों का

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मंत्री ने कॉन्फेंस में मौजूद सभी प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि भारत भूमि पूण्य भूमि है। यह देश किसानों का है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निश्चित ही कॉन्फेंस बहुउपयोगी होगी। योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ किसानों को मिल रहा है।

उद्योग लगाने आह्वान

मंत्री पटेल ने कॉन्फेंस में शामिल देशभर के प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे मध्यप्रदेश में कृषि संबद्ध उद्योग लगाएं। प्रदेश में उपजाउ भूमि, बेहतर जलवायु, सिंचाई की भरपुर सुविधा, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। उद्योग लगाने में राज्य शासन का पूरा-पूरा सहयोग रहेगा।

मंत्री ने किया संवाद

मंत्री ने कॉन्फेंस के शुभारंभ सत्र के समापन पर प्रतिभागियों से टेबल-टू-टेबल जाकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने उद्यानिकी उत्पादों के प्र-संस्करण क्षेत्र में संभावनाओं से अवगत करते हुए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी।

कृषि उद्यानिकी तकनीक पर दिया प्रस्तुतिकरण

कृषि उद्यानिकी तकनीक की प्रथम राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस के तकनीकी सत्र में कृषि उद्यानिकी तकनीकी संस्थाओं के 19 विशेषज्ञों द्वारा विषयवार प्रस्तुतिकरण दिया गया। तकनीकी सत्र में 4 क्षेत्रों पर थीमेटिक सेशन हुआ। इनमें मार्केट लिंकेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट शामिल थे। थीमेटिक सेशन में देश के विभिन्न राज्यों से आये हुए एग्टेक्स स्टार्ट-अप कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। कृषि, उद्यानिकी, नाबार्ड आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने तकनीकी सत्र में भाग लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

ग्रेडिंग नहीं होने से 12 वेयर हाउस पर बुक नहीं हो रहे स्लॉट

सीहोर में दस हजार किसानों से खरीदा 30 हजार टन मूंग

सीहोर। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने इस साल 2 लाख 75 हजार 645 टन मूंग की खरीदी करने का लक्ष्य दिया गया था जबकि 16 जुलाई तक 2 लाख 6 हजार 751 टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। जिस रफ्तार से खरीदी की जा रही है उसके अनुरूप आगामी दो से तीन दिन में यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा। नेफेड द्वारा खरीदी बंद करने के आदेश ने उन किसानों की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है, जिन किसानों ने बिना स्लाट बुक किए ही वेयर हाउस में मूंग तुलवा दिया था। ऐसे हजारों किसानों के ना तो अभी तक स्लाट बुक हो सके हैं और ना ही उनके बिल बन सके हैं। हालांकि नेफेड के आदेश के संबंध में उप संचालक कृषि ने बताया कि नेफेड केंद्र सरकार की एजेंसी है जबकि राज्य सरकार की एजेंसी मार्कफेड है। नेफेड का लक्ष्य पूरा होने के बाद मार्कफेड द्वारा मूंग खरीदी की जाएगी। मूंग खरीदी की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

बिल भी नहीं बन पा रहे

सीहोर जिले में 10134 किसानों से 30 हजार टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है, जबकि 15368 किसानों ने स्लाट बुक कराए हैं। ग्रेडिंग नहीं करने के कारण क्षेत्र के 12 वेयर हाउस ऐसे हैं, जहां ना तो किसानों के स्लाट बुक हो रहे और ना ही किसानों के बिल बन पा रहे हैं। इन पर उपार्जित मूंग की मात्रा जीरो दिखाई दे रही है, जिससे किसानों के स्लाट बुक नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए आ रही परेशानी

ग्रेडिंग नहीं की तो बढ़ सकती है समस्या प्रशासन की सूची में 16 में से 9 गोदाम संचालक ऐसे हैं, जो भंडारित मूंग की ग्रेडिंग करने में लगातार लापरवाही कर रहे हैं। नेफेड अधिकारियों की मानें तो जब तक गोदाम संचालक मूंग की ग्रेडिंग नहीं करते हैं तब तक उक्त गोदामों में भंडारित मूंग की ना तो स्लाट बुक होगी और ना ही उनके बिल बन पाएंगे। ऐसे में गोदाम संचालकों को शीघ्र अति शीघ्र मजदूरों व ग्रेडिंग मशीनों की संख्या में इजाफा कर मूंग की ग्रेडिंग करना होगा, जिससे कि समय रहते किसानों के स्लाट बुक होकर उनके बिल जनरेट हो सके। अन्यथा की स्थिति में गोदाम संचालक मुसीबत में आ सकते हैं।

34 केंद्रों पर किसानों ने तुलवाया

ऑफलाइन दो लाख क्विंटल मूंग जिला सहकारी बैंक भैरूंदा, इटावा व लाड़कुई से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के 34 केंद्रों पर 6032 किसानों ने शासन के नियमों के विपरित व गोदाम संचालकों के कहने पर 2 लाख 23 हजार 30 क्विंटल मूंग ऑफलाइन मोड पर गोदामों में भंडारित किया था। वहीं 1409 किसानों ने स्लाट बुक होने के बाद 37304 क्विंटल मूंग का विक्रय कर अपने बिल बनवाए थे।

मार्कफेड करेगी मूंग की खरीदी गोदाम संचालकों की मनमानी के चलते इस वर्ष मूंग खरीदी के दौरान किसान परेशान हुए हैं। नेफेड द्वारा यदि मूंग खरीदी बंद कर दी जाती है तो राज्य शासन के निर्देश के बाद मार्कफेड मूंग की खरीदी करेगी। किसान चिंतित ना हों। गोदाम संचालक ग्रेडिंग का कार्य पूरी ईमानदारी से करें। सैंपलिंग की बाद भंडारित मूंग की स्लाट बुकिंग व बिल बनने का कार्य शुरू हो जाएगा।
केके पांडे, उप संचालक कृषि

कृषि विकास के लिए नेपाल और भारत मिलकर करेंगे काम, दोनों देशों के कृषि मंत्रियों की भेंट

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नेपाल के कृषि मंत्री डॉ. बेदु राम भुसाल के बीच बुधवार को कृषि भवन, नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। नेपाली मंत्री दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट-2023में भाग लेने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। नेपाली प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कृषि मंत्री श्री तोमर ने नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, खुली सीमा और लोगों के बीच गहरे संपर्कों, घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया।

भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक हैं। ऐसे में नेपाल भारत की मदद से कृषि को मजबूत करना चाहता हैं। इसलिए नेपाल के कृषि मंत्री भुसाल ने श्री तोमर से मुर्रा नस्ल की भैंस प्रदान करने की सहमति ली। सहमति मिलने पर नेपाली मंत्री भुसाल ने श्री तोमर को धन्यवाद दिया और द्विपक्षीय कृषि सहयोग को और बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की। दोनों मंत्री सितंबर-अक्टूबर, 2023 में काठमांडू में देशों के बीच संयुक्त कृषि कार्य समूह की अगले दौर की बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए। बैठक के दौरान दोनों मंत्री, कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने पर भी सहमत हुए, जिसकी प्रक्रिया तेज की जाएगी।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)